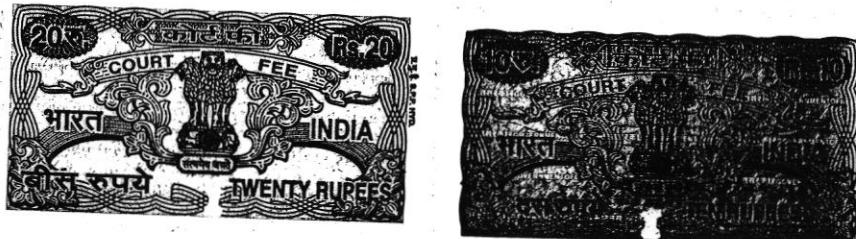


(39)



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक
II/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2018/0030

/2018 जिला-छतरपुर

श्री रमेश चंद्रविलाल गुप्ति
द्वारा आज दि 01.01.18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क छेत्र
दिनांक 05.2.18 नियम।

विरुद्ध ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, भ.प्र. ग्वालियर

शकुन्तला देवी पल्ली श्री देवकीनंदन
रिणारिया
निवासी- लवकुशनगर जिला - छतरपुर
(म.प्र.)

..... आवेदिका
विरुद्ध

दीपक कुमार पुत्र श्री चिरोंजीलाल गुप्ता
निवासी- लवकुशनगर जिला - छतरपुर
(म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर द्वारा
प्रकरण क्रमांक 14/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 01.12.
2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के
अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- 1 यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
- 2 यहकि, माननीय न्यायालय द्वारा आवेदिका के प्रकरण में एक आदेश दिनांक 14.09.2017 को पारित किया गया है, जिसकी किसी भी प्रकार से आवेदिका को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी और न ही माननीय न्यायालय द्वारा जारी ही की गयी। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष पुर्णविलोकन प्रस्तुत किया गया है। जो वर्तमान समय में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है किन्तु इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में

श्री रमेश चंद्रविलाल गुप्ति
01.01.18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/0030

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/03/2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी कर विधिवत कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में प्रथम व्यट्या कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण निगरानी ग्राह्य योग्य हो।</p> <p>दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">~~~~~ प्रशासकीय सदस्य</p> 	